भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2903
उत्तर देने की तारीख 17 दिसंबर, 2025

बीएसएनएल का अपर्याप्त राजस्व सृजन

2903. श्री लालजी वर्माः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अपर्याप्त राजस्व सृजन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों का विस्तृत मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त निष्कर्ष बीएसएनएल में 35 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू करने के निर्णय को उचित ठहराते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की पिछली असफल वीआरएस योजना की तरह बीएसएनएल की वीआरएस योजना को भी विफल होने से रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस योजना के बारे में मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने उन्हें प्रभावी तरीके से दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) सरकार ने सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के साथ-साथ वीआरएस के माध्यम से ऋण पुनर्गठन द्वारा बीएसएनएल की प्रचालन लागत को कम करने के लिए वर्ष 2019 में पहले पुनरुद्धार पैकेज के लिए अनुमोदन दिया। वर्ष 2019 में वीआरएस के कार्यान्वयन के बाद, बीएसएनएल की कर्मचारी

लागत में 51% की कमी आई। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, बीएसएनएल ने वर्ष 2020-21 से प्रचलनात्मक लाभ अर्जित करना शुरू किया।

बीएसएनएल का राजस्व 4जी सेवाओं के रोल आउट में विलम्ब के साथ-साथ मोबाइल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण प्रभावित हुआ है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, बीएसएनएल ने स्वदेशी रूप से विकसित 4जी साइटों के लिए क्रय आदेश दिया है। दिनांक 30.11.2025 तक, कुल 97,401 4जी साइटें संस्थापित की गई हैं और 94,458 साइटें ऑन-एयर हैं। यह उपकरण प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से 5जी में उन्नयन करने योग्य है।

वर्तमान में, इस विभाग में बीएसएनएल में वीआरएस का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****